[श्री हरीश रावत]

परम्परागत यात्रा है। हम सब लोग इस यात्रा का सम्मान करते हैं। इसमें सब की भवनाएं हैं, कसी एक पक्ष या दो पक्ष की भावनाओं का सवाल नहीं है, जिस तरीके से इसको जोड़ने की कोशिश की गई है। ...(व्यवधान)...

Reduction in Kerosene Quota of Andhra Pradesh

SHRI DEVENDER GOUD T. (Andhra Pradesh): Sir, this is regarding reduction in kerosene quota of Andhra Pradesh meant for BPL families.

Sir, kerosene is called 'poor man's fuel' and is used by the poor and the downtrodden for cooking and lightening. The successive Governments have rightly been providing kerosene to poor at subsidized rate. But, if you look at the supply of kerosene to Andhra Pradesh, it has been coming down almost every year.

Earlier, the Government used to supply 1 lakh kilolitres of kerosene to Andhra Pradesh and the State Government used to supply 15 litres for every BPL cardholder. But, in the name of Deepam connections, the Government of India reduced it by 25,000 kilolitres and again by 22,000 kilolitres. This resulted in reduction in quota from 15 litres to 4 litres for the poor living in cities and towns, only 2 litres for people in Mandals and only 1 litre for the poor in villages. As it is not enough, the Government yesterday further cut the quota of kerosene to Andhra Pradesh by 4,000 kilolitres and thereby reduced the quota to 38,800 kilolitres. On the one hand, the poor are demanding for increasing the quota and on the other Government is reducing it without assessing the ground realities. The UPA Government says that its Government is for *Aam Aadmi.* If it is for *Aam Aadmi* on what basis has it reduced the quota to Andhra Pradesh?

I strongly feel that it is a part of the Government's nefarious plan to ultimately stop supply of subsidized kerosene to poor in Andhra Pradesh. It is because Government is seriously thinking of transferring money directly to beneficiaries in the next one year with the objective of stopping kerosene diversion. So, I question: How is the decision to reduce kerosene by 4,000 kilolitres justified to poor? Secondly, by the time Government introduces money transfer to beneficiary, there would not be any supply of subsidized kerosene in Andhra Pradesh. So, this is a larger scheme of Government to deny benefit to the poor.

In view of the above, I demand for de-notifying the order meant to reduce 4,000 kilolitres from this month immediately and also request for restoration of original quota of 1 lakh kilolitres. Thank you.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, this is a very serious issue. ...(*Interruptions*)... We want a discussion on this. ...(*Interruptions*)... It is a bigger issue. ...(*Interruptions*)... I associate myself with the .matter raised by the hon. Member. ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon . Member.

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You are all associated.

Oovercharging by Private Airlines in View of Strike by Air India Pilots

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले दिनों एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल हुई। उस हड़ताल से उत्पन्न स्थितियों का फायदा उठा कर कुछ प्राइवेट एयरलाइंस बेतहाशा और अंधाधुंध किराया बढ़ा रही हैं। पिछले तीन-चार दिनों के अंदर कुछ प्राइवेट एयरलाइंस ने 70 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक किराया बढ़ाया है। इसमें विशेष तौर से जेट एयरलाइंस है, जिसने कि लगातार इन परिस्थितियों में अमानवीय शोषण का काम किया है। इससे संबंधित पूरी डिटेल्स है।

उसपभाध्यक्ष महोदय, आज देश में एयर इंडिया के पायलटों की जो हड़ताल है, उसके बारे में मंत्री जी ने बार-बार बताया है कि वह इसको ठीक करने के लिए उनसे बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं। यह एक अलग विषय है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इन परिस्थितियों में प्राइवेट एयरलाइंस के माध्यम से आम यात्रियों से शोषण का जो काम किया जा रहा है, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। चार दिन तक जो किराया पांच हजार रुपये था, वह 11 हजार रुपये हो गया, जो 10 हजार रुपए तक किराया गया था, वह 25 हजार रुपए हो गया और एक एयरलाइंस ने इस तरह से किराया बढ़ाया, तो उसको देख कर ने low-cost airlines भी उसी तरह किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें एक जो सबसे खतरनाक चीज है, वह यह है कि जिन लोगों ने एक महीने, दो महीने या तीन महीने पहले सस्ते में टिकट बुक कराया था, अब उनको एक नोटिस दिया जाता है, उनको एक सूचना दी जाती है कि चूंकि किराया इतना बढ़ गया है, इसलिए आप एयरलांइस या एयरपोर्ट के कांउटर पर जाकर बढ़ा हुआ किराया पहले जमा कीजिए, तब आपको जाने की इजाजत मिलेगी। यह अपने आप में एक तरह से शोषण है और इस तरह से कुछ प्राइवेट एयरलाइंस आम यात्रियों का शोषण कर रही हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आम यात्रियों के साथ जो इस तरह का शोषण किया जा रहा है, यह लूट है और इस लूट के लिए उन प्राइवेट एयरलाइंस, जो प्राइवेट एयरलाइंस इन परिस्थितियों का लाभ उठा कर आम यात्रियों का शोषण कर रही हैं, को बुलाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि आम यात्रियों का शोषण रुक सके।